भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 317

दिनांक 21.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

ब्रिक्स को टैरिफ का खतरा

317. **श्री रामप्रीत मंडलः**

श्री दिनेश चंद्र यादवः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) ब्रिक्स की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि अमेरिका द्वारा 150 प्रतिशत टैरिफ की धमकी के बाद ब्रिक्स अब बिखरने लगा है;

(ग) वर्तमान में ब्रिक्स के सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है; और

(घ) अमेरिका द्वारा उक्त धमकी के बाद ब्रिक्स के सदस्य देशों की क्या राय है तथा इस मामले में भारत की संभावित भूमिका क्या है?

उत्तर

विदेश मंत्री

(डॉ सुब्रह्मण्यम जयशंकर)

(क) से (घ): विवरण सदन पटल पर रख दिया गया है।

'ब्रिक्स को टैरिफ का खतरा' के संबंध में श्री रामप्रीत मंडल और श्री दिनेश चंद्र यादव द्वारा पूछे गए दिनांक 21.03.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 317 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

वर्ष 2006 में स्थापित ब्रिक्स एक ऐसा मंच है जो अपनी स्थापना के बाद से लगातार प्रगति कर रहा है। यह अपने सदस्य देशों की साझा चिंताओं को दर्शाता है और वैश्विक विचार-विमर्श और नेतृत्व को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण और समावेशी बनाने का प्रयास करता है।

यद्यपि इसकी स्थापना मूलतः चार सदस्य देशों (ब्राजील, रूस, भारत और चीन) के साथ हुई थी, तथापि 2010 में दक्षिण अफ्रीका को भी इसमें शामिल कर लिया गया। उसके बाद, ब्रिक्स का विस्तार हुआ और अब इसमें 11 सदस्य और 9 भागीदार देश शामिल हैं। इसकी सदस्यता में होने वाली वृद्धि और अनेक महत्वाकांक्षी सदस्य देशों द्वारा दिखाई गई रुचि अपने आप में इसकी प्रतिष्ठा और महत्व को अभिव्यक्त करती है।

इसके वर्तमान सदस्य देश हैं: ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ़्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया। इसके साझेदार देश हैं: बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कज़ाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और उज़बेकिस्तान।

ब्रिक्स द्वारा जिन मुद्दों पर चर्चा की जाती है उनमें बहुपक्षवाद को मजबूत करना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार, ब्रेटन वुड्स संस्था, विश्व व्यापार संगठन, आतंकवाद-रोध, स्वास्थ्य, महामारी से निपटने की तैयारी, वित्त और व्यापार, जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली में सुधार, जैव विविधता संरक्षण, मानव अधिकारों का संवर्धन और संरक्षण, भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण और सूखा, वैश्विक जल संकट चुनौती, नौवहन अधिकारों और जहाजों की स्वतंत्रता का उपयोग, अप्रसार और निरस्त्रीकरण, बाह्य अंतरिक्ष गतिविधियाँ और बाह्य अंतरिक्ष में सैन्य प्रतिस्पर्धा की रोकथाम (पीएआरओएस), व्यावहारिक आतंकवाद-रोधी सहयोग, अवैध वित्तीय प्रवाह को रोकना और उनकी रोकथाम, धन शोधन और आतंकवाद संबंधी वित्तपोषण की रोकथाम, दुनिया भर में अवैध नशीली दवाओं के उत्पादन, तस्करी और दुरुपयोग की रोकथाम, अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध की रोकथाम, अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार-रोधी एजेंडा, डिजिटल विभाजन, गलत एवं भ्रामक सूचनाओं का विस्तार और प्रसार को कम करने हेतु आईसीटी का सामर्थ्य, मिश्रित वित्त का उपयोग, अपने सदस्य देशों के अवसंरचना एवं सतत विकास को बढ़ावा देने में न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) की महत्वपूर्ण भूमिका, सीमा-पार भुगतान साधन, सुरक्षित, सुदृढ़, स्थिर, प्रभावी और मुक्त आपूर्ति श्रृंखला, विकास हेतु डाटा की महत्वपूर्ण भूमिका, ई-कॉमर्स, विशेष आर्थिक क्षेत्र, डिजिटल कनेक्टिविटी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा तक पहुंच, एकपक्षीय, दंडात्मक और भेदभावपूर्ण संरक्षणवादी उपाय, ऊर्जा अनुसंधान सहयोग, कार्बन बाजारों की भूमिका,

जलवायु परिवर्तन, भूविज्ञान के क्षेत्र में व्यावहारिक सहयोग और खनिज संसाधनों का तर्कसंगत विकास, सतत विकास और जलवायु स्थिरता हेतु महासागर, किम्बरली प्रक्रिया, परिवहन अवसंरचना, विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका, संचारी और गैर-संचारी रोग, परमाणु चिकित्सा क्षेत्र, रिमोट सेंसिंग उपग्रह अनुप्रयोग, पर्यटन, प्रतिस्पर्धा कानून एवं नीति, कर सहयोग, मानकीकरण के क्षेत्र संबंधी सहयोग, सांख्यिकीय सहयोग, बौद्धिक संपदा, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग, श्रम बाजार में सहयोग, सार्वजनिक क्षेत्र संबंधी लेखा परीक्षा, न्याय के क्षेत्र में सहयोग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी नवाचार (एसटीआई), तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (टीवीईटी), लोगों के बीच आदान-प्रदान, शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना, सतत विकास में संस्कृति की भूमिका, पारंपरिक और स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देना, युवा आदान-प्रदान, अंतर-संसदीय वार्ता, राजनीतिक दलों के बीच संवाद, किफायती आवास और शहरी विकास एवं अनुकूलन को बढ़ावा देना, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका शामिल है।

ब्रिक्स सदस्य देशों द्वारा समय-समय पर क्षेत्रीय राजनीतिक मुद्दों से संबंधित विचार-विमर्श भी किया गया है जिसमें अफगानिस्तान में शांतिपूर्ण समाधान, गाजा में स्थायी युद्ध विराम, लेबनान की स्थिति, सूडान और हैती में मानवीय संकट, यूक्रेन और उसके आसपास की स्थिति, सीरिया की क्षेत्रीय अखंडता शामिल है।

यह स्वाभाविक है कि समसामयिक मुद्दों पर ब्रिक्स सदस्य देशों का दृष्टिकोण भिन्न होगा क्योंकि उन देशों के विकास एवं आय का स्तर अलग-अलग है तथा वे अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हैं। उनकी बैठकों और चर्चाओं का उद्देश्य साझा समाधान प्राप्त करना और वैश्विक व्यवस्था को आकार देने के लिए मिलकर काम करना है। उनका साझा सूत्र बहुध्रुवीयता के प्रति प्रतिबद्धता है।

*****